

औद्योगिक निष्पादन

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि तक सुधरने के बाद, औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि की वृद्धि, जिसमें विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण क्षेत्र शामिल हैं, 2011-12 में 3.5 प्रतिशत तक तथा चालू वर्ष में 3.1 प्रतिशत पर आ गई है। विनिर्माण क्षेत्र, जो उद्योग में सबसे प्रधान क्षेत्र है, ने भी 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः 11.3 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 2.7 प्रतिशत तथा 2012-13 में 1.9 प्रतिशत तक वृद्धि में गिरावट दर्शायी है। बिजली क्षेत्र में वृद्धि भी संयत रही है। खनन क्षेत्र में वृद्धि 2012-13 में 0.4 प्रतिशत रही है, यद्यपि यह 2011-12 में दर्ज की गई 0.63 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि में सुधार को दर्शाती है। उन्नत व्यावसायिक भावनाओं तथा निवेशक ज्ञान तथा अन्य विकासशील देशों में औद्योगिक गतिविधि में आंशिक उछाल से अगले वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास में सुधार होने की आशा है।

9.2 वर्ष 2004-05 को आधार मानते हुए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक देश में औद्योगिक निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है। मासिक आधार पर समेकित की गई तथा 399 उत्पादों/उत्पाद समूहों के आधार पर चालू आई.आई.पी. शृंखला खनन, विनिर्माण तथा बिजली के तीन बड़े समूहों में संकलित है। सूचकांक के रूप में आई.आई.पी. उत्पादन और वृद्धि के दोनों स्तर दर्शाता है। समग्र औद्योगिक निष्पादन जैसा कि आई.आई.पी. द्वारा प्रदर्शित किया गया है, 2012-13 की तीसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत के सुधार से पहले 2012-13 की पहली तिमाही में ऋणात्मक वृद्धि के साथ 2011-12 की पहली तिमाही से संयत रहा है, खनन क्षेत्र का उत्पादन पिछली छः तिमाहियों में कम हुआ है। चालू वर्ष में कमी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस, क्रूड पेट्रोलियम तथा उर्वरक उत्पादों में कमी के कारण थी। विनिर्माण, जो उद्योग में सबसे प्रधान क्षेत्र है, ने भी वृद्धि में मंदी दर्शायी है, जैसीकि विद्युत क्षेत्र ने दर्शायी थी (सारणी 9.1)। तथापि, 9.8 प्रतिशत तक विनिर्माण वृद्धि में सुधार के साथ, जो जून, 2011 के बाद अधिकतम रिकार्ड किया गया है, नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में वृद्धि नकारात्मक रही (-) 0.8 और (-) 0.6 थी।

9.3 उद्योगों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में पिछली छः तिमाहियों में ऋणात्मक वृद्धि रही

है। उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र में वृद्धि में उतार-चढ़ाव रहा है, 2011-12 की चौथी तिमाही में नकारात्मक वृद्धि हुई तथा 2012-13 की दूसरी तिमाही में -07% और तीसरी तिमाही में 3.2% ऋणात्मक रही है तथा बाद में अक्टूबर-नवम्बर, 2012 में सुधरकर 9.25 प्रतिशत तक हो गयी है। अक्टूबर में वृद्धि सामान्य तौर से उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं पर आधारित थी, जो निष्पादन में सुधार दर्शाती हैं। पिछले 20 महीनों में 16.9 प्रतिशत की उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि सर्वाधिक थी (चित्र 9.1)।

9.4 इस अवधि में सभी क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि अस्थिर थी। आईआईपी की मौसम अनुकूल समायोजित वार्षिक वृद्धि दर, जिसने सपाट प्रक्षेप पथ दर्शाया था, गति को नीचे की ओर दर्शाती है। इससे पता चलता है कि आईआईपी वृद्धि शायद मंदी रह सकती है। (चित्र : 9.2)

9.5 आईआईपी विनिर्माण क्षेत्र के 22 समूहों के लिए आंकड़े भी प्रदान करता है। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान संचित रूप से, आईआईपी में 14.5 प्रतिशत भार वाले चार विनिर्माण उप समूहों ने 5 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि रिकार्ड की। सात उप समूहों ने 37.0 प्रतिशत के भारांश के साथ सकारात्मक वृद्धि और

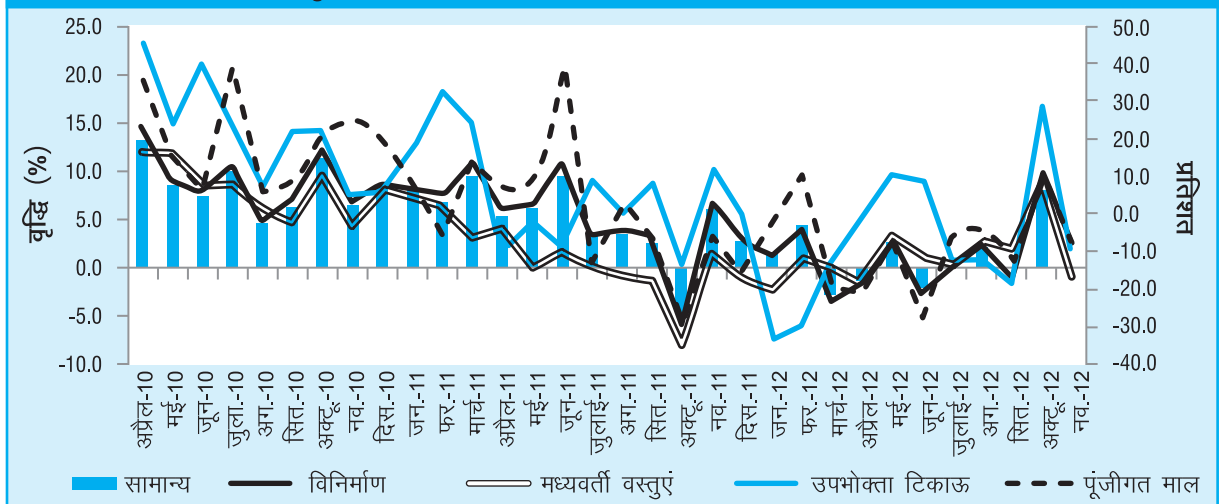
सारणी 9.1 : वृद्धि दर

(प्रतिशत)

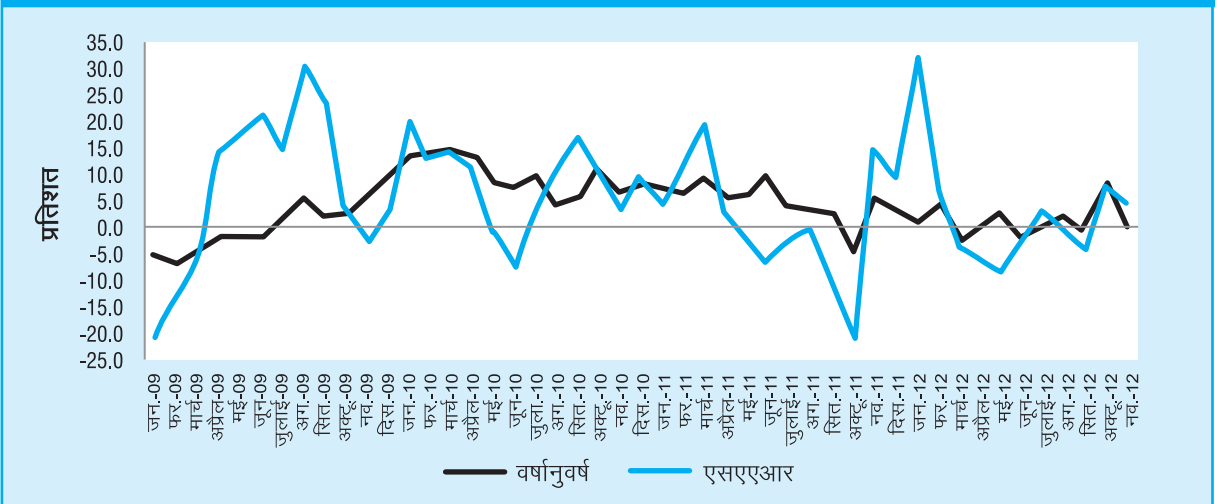
	भारंगश	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
				पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
सामान्य	100.0	8.23	2.89	6.98	3.18	1.18	0.63	-0.28	0.41	2.13
खनन	14.16	5.23	-1.97	0.65	-4.06	-4.22	-0.37	-1.53	-0.69	-3.25
विनिर्माण	75.53	8.95	3.00	7.72	3.36	1.09	0.35	-0.84	0.25	2.61
विद्युत	10.32	5.55	8.16	8.26	10.54	9.57	4.53	6.40	2.83	4.40
बुनियादी वस्तुएं	45.68	5.97	5.48	7.47	7.00	4.36	3.41	3.31	2.21	2.72
पूंजीगत वस्तुएं	8.83	14.75	-3.97	16.99	-5.84	-16.17	-6.85	-20.08	-8.06	-0.95
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.69	7.39	-0.62	1.83	-0.83	-2.90	-0.51	0.83	1.47	2.35
उपभोक्ता वस्तुएं	29.81	8.56	4.37	4.46	4.77	7.72	1.05	3.93	1.40	2.48
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.46	14.16	2.60	2.71	7.87	4.91	-4.13	8.04	0.07	3.17
उपभोक्ता टिकाऊ-भिन्न वस्तुएं	21.35	4.26	5.86	5.93	2.05	10.09	5.28	0.58	2.61	1.92

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

चित्र 9.1: औद्योगिक वृद्धि : बड़े क्षेत्र



चित्र 9.2: आईआईपी गति (समग्र)



11 उपसमूहों ने 24.0 की नकारात्मक वृद्धि, बिजली, मशीनरी और उपस्करों ने 14.6 प्रतिशत की सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। तम्बाकू उत्पादों, कार्यालय लेखांकन तथा अभिकलन मशीनरी तथा लकड़ी व लकड़ी के उत्पादों में ऋणात्मक वृद्धि रही है। धनात्मक पक्ष पर, तथापि, गहन श्रम वाले उद्योगों जैसे वस्त्र तथा परिधान ने पिछली तीन तिमाहियों में सुधार दर्शाया है। तीसरी तिमाही में चमड़े तथा खाद्य उत्पादों

में वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से धनात्मक रही है। आईआईपी के बड़े समूहों के साथ वृद्धि विनिर्माण उप-समूहों में तथा समय के साथ बदलती रही है (सारणी 9.2)।

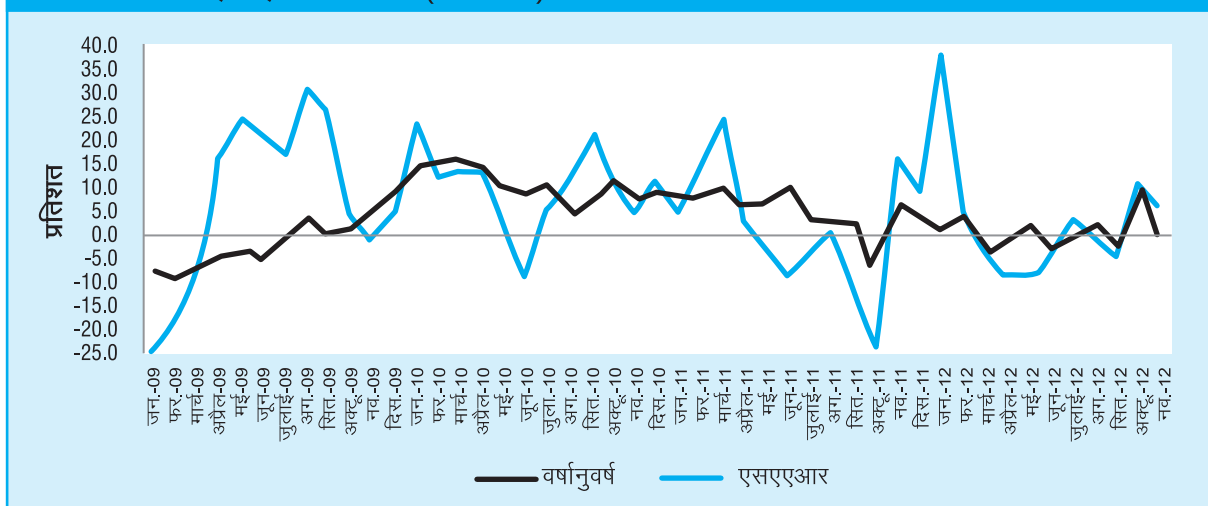
9.6 आईआईपी विनिर्माण की गति कमोबेश समग्र आईआईपी के पथ को प्रदर्शित करती है। मौसम अनुकूल समायोजित वार्षिक श्रृंखलाएं फिलहाल तक नीचे की ओर प्रक्षेपण पथ तथा धीमी प्रगति इंगित करती हैं (चित्र 9.3)।

सारणी 9.2 : विनिर्माण वृद्धि दर (प्रतिशत)

	भार 2010- 2011-		2011-12				2012-13			
	11	12	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	
	पूरा वर्ष									
खाद्य उत्पाद और पेय	7.28	7.0	15.4	17.4	12.3	22.1	11.0	-0.9	0.9	6.7
तंबाकू उत्पाद	1.57	2.0	5.4	4.1	-5.0	16.7	7.2	-5.9	-11.1	-4.2
कपड़ा	6.16	6.7	-1.3	-2.3	-0.3	-4.7	1.8	9.0	5.4	6.2
पहनने के परिधान	2.78	3.7	-8.5	-4.9	-9.4	0.0	-18.2	-6.4	5.4	-0.4
सामान, हैंडबैग, जूते, जीनसाजी, साज और	0.58	8.1	3.7	5.4	7.7	0.2	1.7	8.8	-0.4	9.8
लकड़ी और लकड़ी का उत्पाद	1.05	-2.2	1.8	-8.1	1.7	9.2	4.8	-2.2	-3.5	-15.3
कागज और कागज के उत्पाद	1.00	8.6	5.0	6.7	4.2	5.4	3.8	0.6	1.4	0.3
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डिड मीडिया का पुनः उत्पादन	1.08	11.2	29.6	10.7	7.4	41.9	55.9	13.6	16.7	-14.3
कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद और नाभकीय ईंधन	6.72	-0.2	3.5	6.0	4.7	1.8	1.7	1.6	7.9	13.1
रसायन और रसायन उत्पाद	10.06	2.0	-0.4	3.5	-2.1	-0.5	-2.3	-1.2	6.4	3.0
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	2.02	10.6	-0.3	-2.5	-0.1	-2.5	3.9	6.9	-2.1	-0.2
अन्य धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	4.31	4.1	4.8	-0.5	6.2	8.4	5.2	7.5	-0.2	-4.3
बुनियादी धातुएं	11.34	8.8	8.7	15.6	13.6	4.6	2.4	2.3	0.2	5.0
निर्मित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपस्कर का छोड़कर	3.08	15.3	11.2	15.8	12.1	12.9	6.2	2.9	0.6	-9.7
मशीनरी और उपस्कर एन०ई०सी०	3.76	29.4	-5.8	-1.7	-2.0	-3.8	-13.2	2.4	-3.8	-10.4
कार्यालय, लेखाकरण और संगणन मशीनरी	0.31	-5.3	1.6	28.2	0.1	-5.3	-9.5	-1.8	-21.5	-14.7
बिजली मशीनरी और उपकरण	1.98	2.8	-22.2	25.5	-27.7	-49.5	-26.4	-43.7	-10.5	33.2
रेडियो, टीवी और संचार के उपस्कर व उपकरण	0.99	12.7	4.3	-6.7	16.5	11.6	-5.0	18.3	4.1	4.5
चिकित्सा, प्रिसिजन और दृष्टि संबंधी यंत्र, घड़ियां और दीवार घड़ियां	0.57	6.8	10.9	-2.2	-1.9	36.0	12.2	15.5	7.4	-17.7
मोटर वाहन, ट्रैलर और अर्ध-ट्रैलर	4.06	30.2	10.8	20.1	8.0	7.6	9.0	0.3	-5.6	-4.2
अन्य परिवहन उपस्कर	1.82	23.2	11.9	19.1	16.3	11.1	3.1	0.7	-4.7	0.4
फर्नीचर, अन्य विनिर्माण	3.00	-7.5	-1.8	-0.1	-0.5	-6.4	-0.6	-8.2	-9.2	7.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

चित्र 9.3: आईआईपी की गति (विनिर्माण)



वृद्धि मंदी क्यों है?

9.7 औद्योगिक वृद्धि में कमी, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, मुख्य रूप से निवेश कम वृद्धि, कारपारेट क्षेत्र के कम लाभ, ऋण प्रवाहों की वृद्धि दर में कमी तथा दुर्बल वैश्विक आर्थिक समुत्थान के कारण है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

9.8 औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ), जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत तथा निर्माण आते हैं, ने 2004-05 से 2011-12 के दौरान 13.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि रिकार्ड की है।

2008-09 तथा पुनः 2011-12 के दौरान वृद्धि ऋणात्मक हो गयी। 2007-08 में संयुक्त उद्योग क्षेत्र देश में कुल जीसीएफ (मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ कर) का 55 प्रतिशत रहा है, जो 2011-12 में कम हो कर 44.4 प्रतिशत रह गया (सारणी 9.3)।

9.9 अर्थव्यवस्था के लिए कुल जीसीएफ में उद्योग में जीसीएफ के समग्र हिस्से में कमी तथा 2008-09 तथा 2011-12 के दौरान समग्र ऋणात्मक वार्षिक वृद्धि, मौटे तौर पर पंजीकृत तथा अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में जीसीएफ में ऋणात्मक वृद्धि के कारण थी। समग्र जीसीएफ में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2007-08 में 38.1 प्रतिशत के शीर्ष से 2011-12 में गिरकर

सारणी 9.3 : उद्योग में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

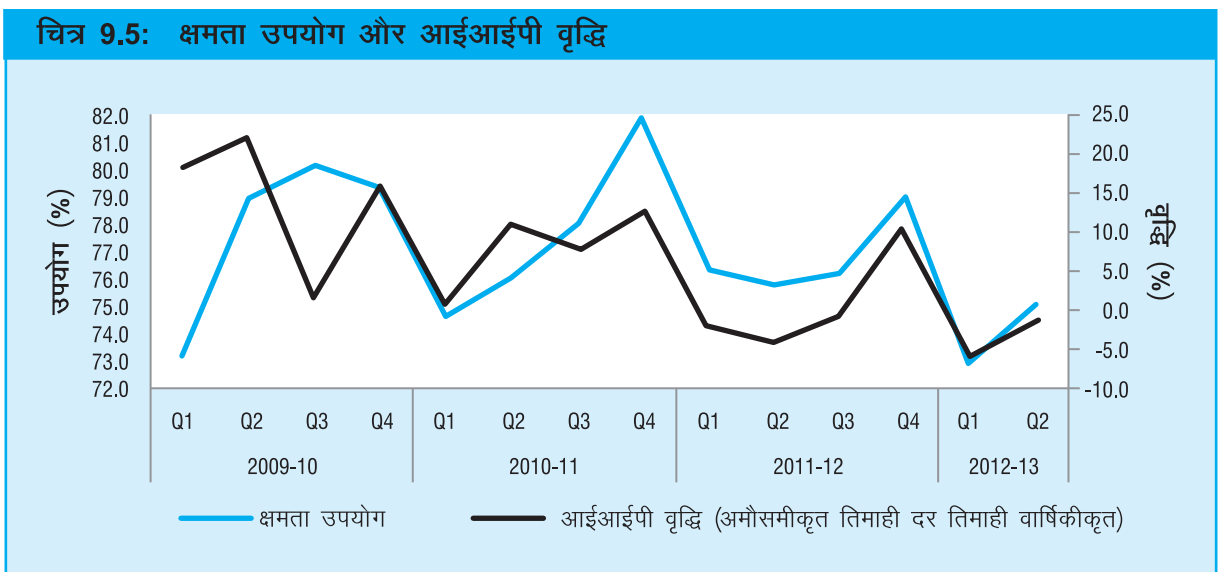
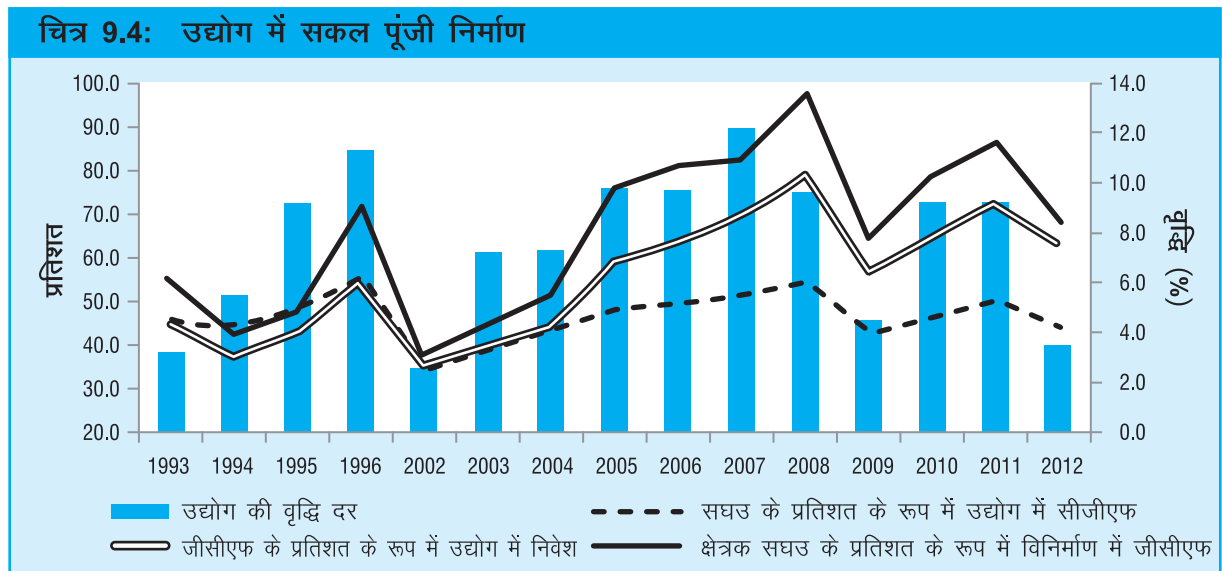
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धिदर (प्रतिशत)	46.7	18.3	22.0	24.7	-24.5	24.2	22.3	-10.8
समग्र जीसीएफ में उद्योग के क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)								
खनन	3.7	4.4	4.4	4.3	3.6	3.6	3.8	3.8
विनिर्माण	34.1	34.2	34.8	38.1	26.8	32.9	34.7	27.9
पंजीकृत विनिर्माण	24.3	29.0	27.9	32.5	24.1	27.8	29.7	24.9
अपंजीकृत विनिर्माण	9.7	5.3	6.9	5.6	2.7	5.1	5.1	3.0
विद्युत	5.3	5.5	5.6	5.4	6.3	6.2	6.6	6.8
निर्माण	5.4	4.9	7.0	7.2	5.7	4.8	5.3	6.0
जीसीएफ में उद्योग का हिस्सा	48.4	49.0	51.8	54.9	42.5	47.5	50.4	44.4
उद्योग में जीसीएफ का हिस्सा, इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में	59.0	63.6	69.2	78.7	56.9	64.7	72.5	62.4
विनिर्माण में जीसीएफ का हिस्सा, विनिर्माण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में	76.0	81.1	83.2	97.3	64.1	78.3	86.8	68.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

27.9 प्रतिशत तक रह गया है। चूंकि जीडीपी का प्रतिशत उद्योग से उत्पन्न होता है, जीसीएफ का हिस्सा 2007-08 में 78.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, यद्यपि 2011-12 में यह कम होकर 62.4 प्रतिशत रह गया। 2008 में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र की जीसीएफ इस क्षेत्र की 97 प्रतिशत आय से अधिक स्तर पर पहुंच गया था।

9.10 उद्योग में निवेश सामान्य रूप से उछला है तथा इसने अर्थव्यवस्था के समग्र जीसीएफ में अपने हिस्से में वृद्धि दर्शायी है। यह हिस्सा सुधार के बाद की अवधि में 1995-6 में अर्थव्यवस्था में कुल जीसीएफ के 56.2 प्रतिशत तक पहुंच कर शीर्ष पर था। जीसीएफ की वृद्धि दर, तथापि, उद्योग की वृद्धि दर के अनुसार चलती है। इस क्षेत्र ने पूंजी निर्माण के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवंटित करना जारी रखा है। (चित्र 9.4)

9.11 निवेश में वृद्धि में कमी के साथ (समग्र उद्योग क्षेत्र में निवेश वास्तव में 2011-12 में कम हुआ है), समग्र रूप से ज्यादा क्षमता बनी रहनी प्रतीत होती है। चित्र 9.5, जो आईआईपी तथा क्षमता उपयोग की बिना रूझान की वृद्धि दर्शाता है, यह इंगित करता है कि आईआईपी वृद्धि में कमी के साथ, क्षमता उपयोग में भी कमी रही है। क्षमता उपयोग, जो भारतीय रिजर्व बैंक की आदेश पुस्तिकाओं के 19वें दौर, वस्तु सूचियों तथा क्षमता उपयोग द्वारा मापा जाता है, 2012-13 की पहली तिमाही तक सतत गिरावट दर्शाता है तथा दूसरी तिमाही में ऊपर की ओर संयत रूझान दर्शाता है। क्षमता उपयोग तथा बिना रूझान वाली आईआईपी के बीच विस्तृत सह-संचलन है।



सारणी 9.4 : औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण लगाना

(₹ बिलियन)

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
उद्योग	14461	17656	16541	17121	17964	18999	19772	19890	20752
विनिर्माण	9169	11106	10296	10771	11315	12040	12617	12498	12994
खनन	198	283	263	273	285	309	356	367	393
विद्युत	2317	3032	2865	2966	3080	3216	3264	3537	3745
निर्माण	453	523	504	496	531	561	581	593	566
अन्य	2323	2714	2613	2616	2752	2873	2954	2895	3054
संवितरित ऋण में हिस्सा (प्रतिशत)									
विनिर्माण	63.41	62.90	62.25	62.91	62.99	63.37	63.81	62.84	62.61
खनन	1.37	1.60	1.59	1.59	1.59	1.63	1.80	1.85	1.89
विद्युत	16.02	17.17	17.32	17.32	17.15	16.93	16.51	17.78	18.05
निर्माण	3.13	2.96	3.05	2.89	2.96	2.95	2.94	2.98	2.73
अन्य	16.06	15.37	15.80	15.28	15.32	15.12	14.94	14.56	14.72
ऋण प्रवाह की वृद्धि दर (प्रतिशत)									
उद्योग	26.48	22.10	24.82	22.57	21.21	20.24	19.54	16.17	15.52
विनिर्माण	19.39	21.12	19.90	22.92	21.08	20.62	22.54	16.04	14.83
खनन	27.97	42.43	41.54	42.16	41.40	44.42	35.08	34.42	37.94
विद्युत	48.19	30.83	41.44	34.15	27.06	23.30	13.94	19.26	21.58
निर्माण	16.30	15.45	14.71	11.04	20.16	15.90	15.35	19.64	6.60
अन्य	41.20	16.82	29.74	10.98	14.33	14.34	13.06	10.66	10.96

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

औद्योगिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह

9.12 निवेश में गिरावट मौटे तौर पर दो कारणों से है: लाभ में कमी तथा औद्योगिक क्षेत्र में ऋण की वृद्धि दर में कमी। उद्योग में ऋण प्रवाह की समग्र वृद्धि दर 2010-11 में औसत 26.48 प्रतिशत से 2012-13 की तीसरी तिमाही में औसतन 15.52 प्रतिशत तक कम हुई है। वृद्धि में कमी ऋण संवितरण में समग्र वृद्धि के साथ निर्माण क्षेत्र के लिए समान आकृतिकार की थी और जो 2010-11 में 16.3 प्रतिशत से 2012-13 की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत तक कम हो गया था। खनन और विद्युत क्षेत्रों में भी ऋण संवितरण की वृद्धि में कमी हुई है (चित्र 9.4)।

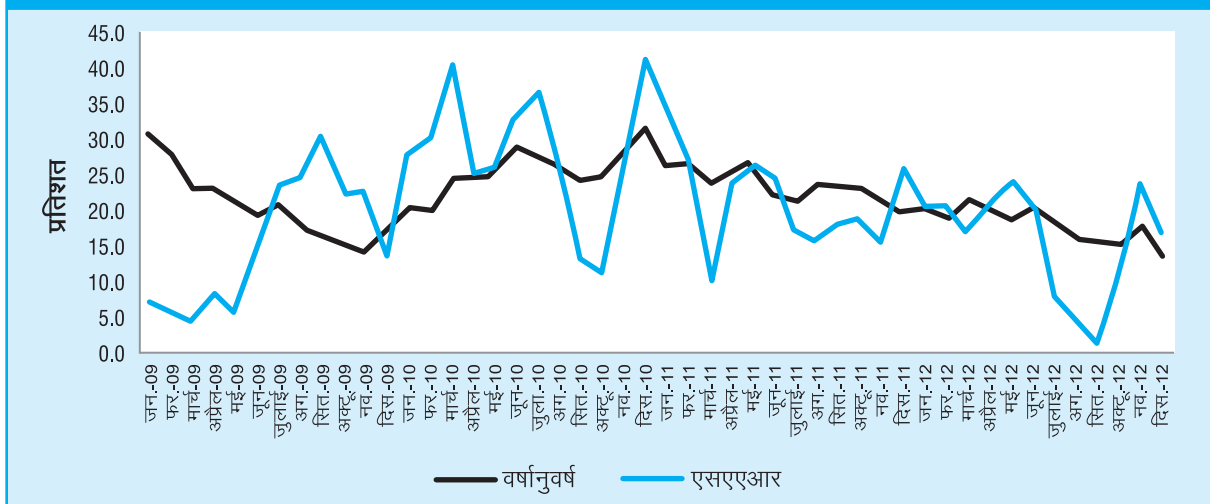
9.13 मौसम अनुकूल समायोजित वार्षिक दर के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि की गति नीचे की ओर प्रक्षेपण पथ दर्शाती है जिससे पता चलता है कि ऋण में वृद्धि कमजोर है (चित्र 9.6)।

9.14 विनिर्माण में, जिसका औद्योगिक क्षेत्र में कुल ऋण के संवितरण में 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा था, वृद्धि में कमी सभी क्षेत्रों में संवितरित नहीं की गई थी, यद्यपि अधिकतर क्षेत्रों ने वृद्धि

में कमी दर्शायी थी। रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अंश ने, जिसका 2010-11 में कुल बकाया ऋण में 16 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा था, चालू वर्ष में ऋण की वृद्धि दर में वृद्धि दर्शायी है। परिवहन उपस्करों, रत्न तथा आभूषण तथा अन्य विविध उद्योगों ने ऋण प्रवाह की वृद्धि दर में काफी गिरावट दर्शायी है (सारणी 9.5)।

9.15 तथापि, उद्योग में ऋण प्रवाहों वाले संचित संसाधन प्रवाहों, बैंकों द्वारा एसएलआर-भिन्न निवेश और गैर बैंकिंग चैनलों के प्रवाहों ने आशावाद का कारण दर्शाया है। अभी तक (11 जनवरी, 2013 तक) वित्तीय वर्ष के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह सारणी 9.5 में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में ज्यादा रहा है। प्रवाह में वृद्धि बैंक तथा गैर बैंक संसाधनों दोनों के कारण हुई है, यद्यपि परिवर्ती ने प्रबल भूमिका निभायी है। घरेलू संसाधनों में, गैर खाद्य ऋण तथा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) निवेश, व्यावसायिक कागज के निवल निर्गम, आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण ने पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में काफी वृद्धि दर्शायी है।

चित्र 9.6: औद्योगिक ऋण की चाल



सारणी 9.5 : व्यावसायिक क्षेत्रों में संसाधन प्रवाह

(₹ बिलियन)

	अप्रैल-मार्च			अप्रैल से जनवरी 11	
	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13P
क. समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण तथा गैर-सांख्यिक नकदी अनुपात (एसएल आर) निवेश	4786	7110	6764	3953	4397
ख. गैर बैंकों से प्रवाह (बी1+बी2)	5850	5341	5338	4154	5232
बी1. घरेलू स्रोत	3652	3011	3034	1913	2951
बी2. विदेशी स्रोत	2198	2330	2304	2241	2281
ग. संसाधनों का कुल प्रवाह	10,636	12,451	12,102	8107	9629

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: अ: अनतिम

वित्तपोषण के विदेशी संसाधनों (दिसम्बर, 2012 तक) ने भी पिछले वर्ष की तुलना में लाभों में वृद्धि दर्ज की है, जो मुख्य रूप से उच्च विदेशी वाणिज्यिक उधारों के कारण है।

कारपोरेट निष्पादन

9.16 मंदे औद्योगिक प्रदर्शन ने कारपोरेट निष्पादन को भी प्रभावित किया है। कारपोरेट क्षेत्र की बिक्री की वृद्धि दर विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में, 2010-11 की पहली तिमाही में 28.8 प्रतिशत के औसत से 2012-13 की दूसरी तिमाही में नवीनतम तिमाही जिसके आंकड़ों का तुलनात्मक सैट उपलब्ध है, 11.4 प्रतिशत तक कम हुई है। वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ब्याज व्यय की वृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई थी जो 2011-12 की दूसरी तिमाही में, 41.5 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी। बिक्री में वृद्धि दर में कमी के साथ बिक्री के निवल लाभ के अनुपात में भी कमी हुई है। लाभ और बिक्री का अनुपात जो 2010-11 की पहली दो तिमाहियों में औसत 8 प्रतिशत था, 2011-12 की तीसरी तिमाही में 3.6 प्रतिशत तक कम हुआ है तथा अंतिम 3 तिमाहियों में 5 से 6

प्रतिशत की सीमा में रहा है (सारणी 9.6)। 2012-13 की दूसरी तिमाही में ब्याज भुगतान की वृद्धि 10 प्रतिशत तक कम हुई है जो रेपो दर के साथ ब्याज दर के स्थिरीकरण को प्रदर्शित करती है जो अप्रैल 2012 से जनवरी 2013 तक स्थिर रही है। परिणामस्वरूप, 2012-13 की दूसरी तिमाही में लाभ कुछ बढ़ा है, आंशिक रूप से अन्य आयों में तेजी से वृद्धि के कारण। जैसा कि अध्याय 4 में पहले ही दर्शाया गया है, कारपोरेट क्षेत्र के पास गैर खाद्य विनिर्माण के लिए मुद्रास्फीति सहित सीमित मूल्य निर्धारण शक्ति थी और शीर्ष मुद्रास्फीति की अपेक्षा काफी कमी रिकार्ड की गई। पूंजीगत वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से कम रही है।

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र विनिर्माण निष्पादन में अड़चन बनी रहेगी

9.17 कम कारपोरेट लाभप्रदता तथा उद्योग में ऋण प्रवाह की वृद्धि में कमी ने भी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के निष्पादन पर अपना प्रभाव

सारणी 9.6 : निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कम्पनियों की बिक्री और व्यय में वृद्धि

मद	2010-11				2011-12				2012-13	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
कंपनियों की संख्या	1900	1933	1961	1953	1935	1922	1910	1887	2003	1954
	वृद्धि दरें (वर्षानुवर्ष प्रतिशत में)									
बिक्रियां	28.8	21.2	19.0	23.3	24.9	19.7	19.5	15.2	13.0	11.4
बिक्री माल में परिवर्तन	354.0	-46.5	89.0	214.9	-42.8	-24.0	117.7	-53.6	-40.1	224.3
जिसका व्यय	34.5	22.5	21.1	26.5	25.0	23.2	25.9	16.2	15.6	12.5
कच्ची सामग्री	40.6	21.9	20.9	30.5	28.8	23.8	26.0	17.0	13.4	14.7
स्टाफ लागत	16.9	20.4	21.1	18.2	17.5	15.3	13.5	10.8	13.2	12.5
विद्युत और ईंधन	13.1	15.6	22.9	20.7	27.9	23.3	25.5	24.4	19.1	15.9
अन्य आय	-28.5	69.5	10.3	-30.5	45.8	-3.0	40.4	72.3	15.8	71.1
ब्याज व्यय	10.9	7.8	13.7	23.1	20.5	41.5	38.6	30.0	38.2	10.0
निवल लाभ	8.2	10.9	14.6	7.1	9.6	-18.3	-43.9	-9.8	-18.1	28.7
बिक्रियों में निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	8.0	8.1	7.7	7.4	6.8	5.4	3.6	6.1	5.0	6.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

डाला है जिसने बाद में समग्र औद्योगिक वृद्धि को प्रभावित किया है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की आईआईपी आधारित वृद्धि दर 2010-11 में 14.8 प्रतिशत पर मजबूत थी, उसके बाद इस क्षेत्र ने सतत रूप से मंदी का अनुभव किया। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम होकर 10.1 प्रतिशत रह गया। पूंजीगत वस्तुओं के उप-क्षेत्रों की ओर जाते हुए, हम मशीनरी तथा उपस्कर, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन खंडों में लगातार ऋणात्मक वृद्धि देखते हैं (सारणी 9.7)। परिवहन खंड में कमी मुख्य रूप से व्यावसायिक वाहनों तथा तिपहियों के उत्पादन में कमी के कारण थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में आने वाले और ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले मुख्य वैयक्तिक

उत्पाद कंप्यूटर, यूपीएस, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल इंजुलेटिड, टरबाइन तथा निर्माण मशीनरी है।

9.18 निवेश, मशीनरी और विद्युत मशीनरी खंडों में आयात प्रतिस्थापन में कमी तथा नई परियोजनाओं की संख्या में गिरावट ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 2009-2011 में सुदृढ़ वृद्धि के बाद परिवहन खंड में कमी मुख्य रूप से व्यावसायिक वाहनों तथा तिपहियों की घरेलू मांग में कमी के कारण रही है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में रुपये के मूल्यहास तथा कम घरेलू मांग के कारण मुख्य पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कमी हुई है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के

सारणी 9.7 : पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा दूसरे घटकों की आईआईपी आधारित वृद्धि दर

	2009-10	2010-11	2011-12	(प्रतिशत) अप्रैल-दिस. 2012-13
बने-बनाए धातु उत्पाद	10.2	15.3	11.2	-2.4
मशीनरी और उपस्कर	15.8	29.4	-5.8	-3.8
कार्यालय, लेखांकन तथा अनुपूरक मशीनरी	3.8	-5.3	1.6	-12.5
विद्युत मशीनरी	-13.5	2.8	-22.2	-14.6
मोटर वाहन, आदि	29.8	30.2	10.8	-3.2
अन्य परिवहन उपस्कर	27.7	23.2	11.9	-1.2
पूंजीगत वस्तुएं	1.0	14.8	-4.0	-10.1
विनिर्माण	4.8	9.0	3.0	0.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सारणी 9.8 : अमरीकी डालर में मूल्यित पूंजीगत वस्तुओं के आयात की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-दिस.)
1. मशीन औजार	-27.6	36.1	32.7	-3.6
2. बिजली के अलावा मशीनरी	-9.4	21.0	26.6	-6.7
3. विद्युत मशीनरी	-16.1	23.4	24.1	-6.5
4. परिवहन उपस्कर	-11.5	-2.1	19.2	4.5
5. परियोजना संबंधी वस्तुएं	47.9	30.8	42.1	-15.4
6. धातुओं का विनिर्माण	-26.1	38.5	27.5	3.1
7. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	-10.7	26.8	23.0	-8.2
8. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप	32.0	-32.5	44.3	-60.8

स्रोत : वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आयात में क्रमशः 28 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मशीनरी, विद्युत मशीनरी, मशीन टूल्स तथा परियोजना संबंधी वस्तुओं के आयात में काफी तेजी आयी है। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान, रुपये का मूल्य ह्रास और कमजोर घरेलू मांग के कारण महत्वपूर्ण पूंजीगत माल का आयात गिरा है। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान समग्र आयात में पूंजीगत वस्तुओं का हिस्सा 18-20 प्रतिशत की सीमा में रहा है। अप्रैल-दिसम्बर, 2012-13 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं का कुल आयात 365 बिलियन अमरीकी डालर के कुल आयात में लगभग 68.35 बिलियन अमरीकी डालर था।

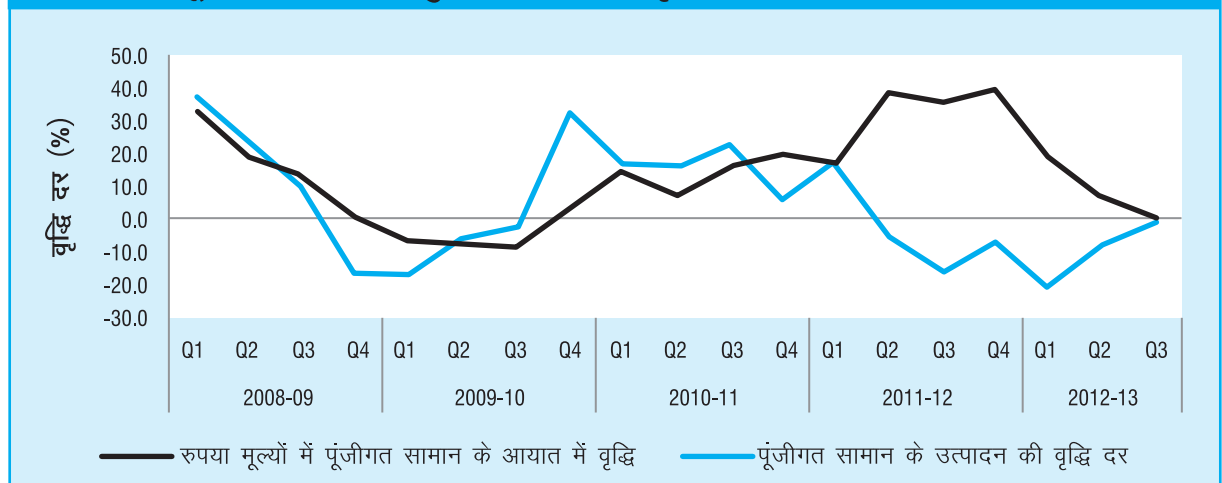
9.19 पूंजीगत वस्तुओं के आयात के तिमाही रुझान तथा पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का विश्लेषण 2011-12 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अचानक तेजी दर्शाता है और इन्होंने भारी मशीनरी, निर्माण मशीनरी तथा विद्युत मशीनरी के घरेलू खंडों को प्रभावित किया है। परंतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में तेजी से गिरावट आयी है, विशेष रूप

से दूसरी तिमाही के दौरान (चित्र 9.7)। चूंकि आईआईपी आधारित पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र का उत्पादन चालू वर्ष की (पहली तिमाही में) 20.1 प्रतिशत तथा (दूसरी तिमाही में) 8.1 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 0.1 प्रतिशत तक कम हुआ है, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी घरेलू निवेश तथा परियोजना व्यय में मंदी के कारण है।

क्या औद्योगिक मंदी समाप्त हो रही है?

9.20 अक्टूबर 2012 में औद्योगिक विकास में तेजी के बावजूद, इस बात के मिश्रित संकेत हैं कि क्या मंदी का चरण समाप्त हो गया है अथवा चालू मंदी कुछ बाद तक बनी रहेगी। कम से कम दो कारक हैं जो औद्योगिक मोर्चे पर कुछ आशा दर्शाते हैं। उत्पादों/उत्पाद समूहों की आवृत्ति के वितरण से संबंधित आंकड़े जो आईआईपी का निर्माण करते हैं, यह दर्शाते हैं कि ऋणात्मक वृद्धि वाले उत्पादों की संख्या 2011-12 की चौथी तिमाही में 182 से कम होकर अक्टूबर-नवम्बर, 2012 में 160 रह गई है। ऋणात्मक

चित्र 9.7: पूंजीगत सामान की तुलनात्मक तिमाही वृद्धि दर (उत्पादन और आयात)



सारणी 9.9 : उत्पादों का उनकी वृद्धि के संदर्भ में आवृत्ति वितरण

उत्पादों की संख्या/उत्पाद समूह	2010-11		2011-12				2012-13		
	2010-11	2011-12	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	अक्टू.
			तिमाही	तिमाही	तिमाही	तिमाही			
ऋणात्मक	102	163	151	168	179	182	175	188	160
0-5	82	92	74	65	81	77	60	67	75
6 से 20	137	109	105	103	89	80	101	83	97
20 और अधिक	81	38	72	66	53	63	66	64	70
कुल वस्तुएं	402	402	402	402	402	402	402	402	402
भार (प्रतिशत)									
ऋणात्मक	22.22	28.60	28.53	36.96	39.53	41.64	45.01	41.38	29.33
0-5	20.86	29.79	16.69	18.10	18.57	27.73	11.42	27.62	34.74
6 से 20	42.58	33.16	41.25	32.44	31.58	23.38	38.01	21.74	24.36
20 और अधिक	14.34	8.44	13.52	12.50	10.33	7.25	5.57	9.25	11.57
कुल भार	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

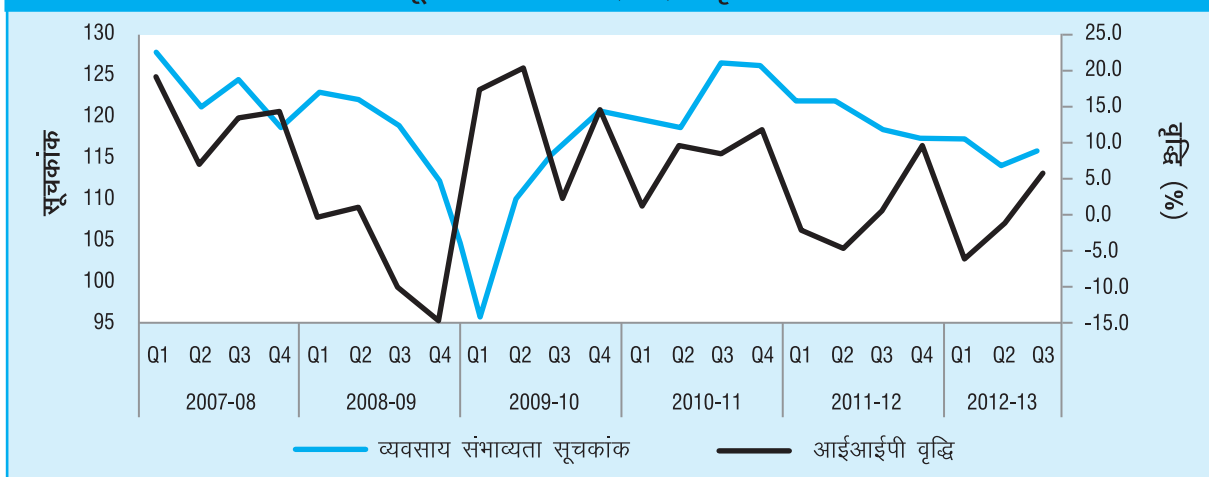
टिप्पणी : आईआईपी के 399 उत्पाद/उत्पाद समूह हैं तथा यह विद्युत और खनन को प्रत्येक को एक उत्पाद मानता है। खनन क्षेत्र, कच्चे पेट्रोलियम, कोयले, प्राकृतिक गैस तथा अन्य के रूप में विभाजित है, क्योंकि पहले तीन उत्पाद को उद्योगों में कवर हैं।

वृद्धि वाले उत्पादों का भार 2011-12 की दूसरी तिमाही में 40-45 प्रतिशत की औसत से अक्टूबर-नवम्बर, 2012 में 29.3 प्रतिशत तक कम हुआ है। उत्पादों तथा उनके भारों की संख्या तो 20 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्शाती है, ऊपर की ओर हल्का रुझान दर्शा रही है (सारणी 9.10)।

9.21 आशा के लिए बनाए जा रहे आंकड़ों का दूसरा सैट आरबीआई का व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक है, जिसने पिछली छः तिमाहियों के लिए लगातार ऋणात्मक वृद्धि के बाद 2012-13 की तीसरी तिमाही में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है। व्यवसाय अपेक्षा

सूचकांक से सही रूप से निकटता से आईआईपी वृद्धि का पता लगता है तथा यह आईआईपी वृद्धि में कमी को समाप्त करने की संभावना का सुझाव देता है। वैश्विक रूप से, औद्योगिक गतिविधि में तेजी रही है। विनिर्माण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में विश्वास निर्माण और अन्य उपाय भी औद्योगिक सुधार सुसाध्य बनाने में मदद करेंगे (बॉक्स 9.2) आईआईपी, आईआईपी विनिर्माण और उद्योग को एसएएआर पर आधारित ऋण में वृद्धि की अधोमुखी चाल हालांकि यह इंगित करती है कि निम्न औद्योगिक वृद्धि का चरण कुछ और समय तक जारी रहेगा।

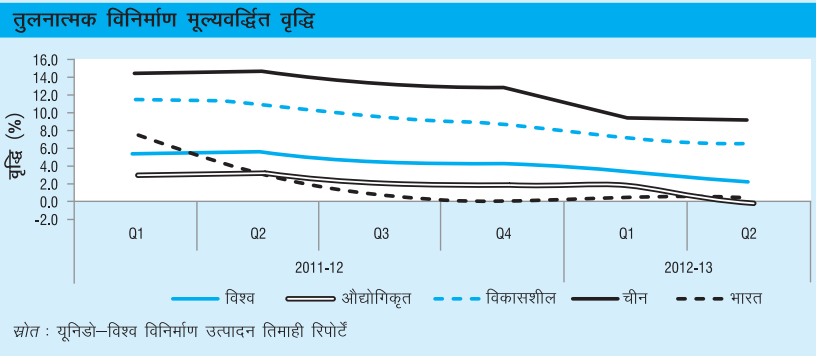
चित्र 9.8: व्यवसाय संभाव्यता सूचकांक और आईआईपी वृद्धि



बॉक्स 9.1 : भारत और विश्व विनिर्माण उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति

भारत शीर्ष दस विनिर्माणकारी देशों में एक है यद्यपि कुल विनिर्माण मूल्य वर्धन (एमवीएम) में इसका अंश केवल लगभग 1.8 प्रतिशत है। औद्योगिक वृद्धि पर पश्च-संकट आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत सहित विकासशील देशों में अपेक्षाकृत नरम रहा है फिर भी विनिर्माण मूल्य वर्धन (एमवीएम) में अधोमुखी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण रही है। देशों में गिरावट की गहनता में भिन्नता आई है जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है। विश्व विनिर्माण मूल्य वर्धन की वृद्धि दर 2011-12 की पहली तिमाही में 5.4 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 की दूसरी तिमाही में 2.2 प्रतिशत हो गई। चीन की एमवीएम वृद्धि दर इसी अवधि के दौरान 14.3 प्रतिशत से गिरकर 7.3 प्रतिशत हो गई लेकिन भारत के संबंध में गिरावट की दर में तेजी आई है चूंकि वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से गिरकर 0.2 प्रतिशत हो गई। भारत और अन्य प्रमुख विनिर्माण देशों के बीच 34 समूह स्तर के एमवीएम की विश्लेषण में तेज भिन्नता को इंगित करती है। मशीनरी और उपकरण के उत्पादन में जो कि पूंजी वस्तु क्षेत्र के प्रमुख घटकों में एक रहा है, भारत के संबंध में इस गिरावट के मुकाबले संयुक्त राज्य, कनाडा, चीन, मलेशिया में तीव्र वृद्धि दर पर रहा है। पूंजी वस्तुओं और उच्च तकनीकी क्षेत्रों के अन्य घटकों में इसी प्रकार का प्रारूप देखा गया। इसका कारण प्रतिस्पर्धी अलाभ रहा है। इस कारण भारत की तकनीकी का निम्न स्तर, उच्च निर्दिष्ट लागतों और कमजोर गुणवत्ता वाली अवसंरचना के प्रतिस्पर्धी अलाभ में होना है। 1995 से 2009 तक का दीर्घावधिक प्रवृत्ति विश्लेषण यह दर्शाता है कि परिष्कृत उत्पादों के एमवीएम में शेयर के बढ़ने में भारत काफी पीछे रहा है। इसने वस्त्र, पहनने के परिधान और चर्म उत्पादों जैसे श्रम गहनता क्षेत्रों में कम मध्यम उत्पादों में बेहतर रहा है। यद्यपि भारत का शेयर इन क्षेत्रों में चीन के मुकाबले कम रहा है जोकि इन तीनों क्षेत्रों में प्रभुत्व रखता है।

विश्व विनिर्माण का 2 अंकीय उद्योग स्तर का विश्लेषण यह इंगित करता है कि वैश्विक रूप से हाल में हुए वर्षों में पांच तेजी से बढ़ते क्षेत्र-कार्यालय लेखांकन और संगणन मशीनरी, रेडियो, टीवी और संचार के उपस्कर, बिजली मशीनरी और उपकरण अन्य परिवहन; और बुनियादी धातु थे। बुनियादी धातु को छोड़कर, सभी क्षेत्र मध्यम और उच्च तकनीकी गतिविधियां हैं। हाल में हुए वर्षों में कुछेक तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में भारत का निष्पादन निराशाजनक रहा है। इसके विपरीत, चीन 22 औद्योगिक क्षेत्रों में से 15 में कुल एमवीएम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा रखता है। भारत का शेयर कुछेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा संकलित अद्यतन प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक निष्पादन सूचकांक (सीआईपी) में 118 देशों में से भारत का स्थान 42वां है। यह रैंक 2005 में भी इतना ही था। चीन का स्थान 5वां है।



संगठित विनिर्माण

9.22 सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2010-11 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनन्तिम परिणामों को जारी किया है। वार्षिक उद्योग सर्वे 10 अथवा अधिक कामगारों के संगठित विनिर्माण नियोजन वाला सबसे व्यापक सर्वे है। 2010-11 में सकल घरेलू वर्द्धन (जीवीए) में 19.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो 2008-09 में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2009-10 में 14.1 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्शाता है। अन्य सकारात्मक विशेषता रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन उद्योगों में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या में 2001-02 से लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इन उद्योगों में समग्र नियोजन में 2010-11 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संगठित विनिर्माण

उद्योगों में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 2001-02 में 7.8 मिलियन नियोजन की तुलना में 2010-11 में बढ़कर 12.7 मिलियन हो गई। संगठित विनिर्माण में नियोजन में वृद्धि संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 2009-10 के सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या में तेज गिरावट रही। जबकि नियोजन और उद्योग में ईंधन दक्षता पर चिंता बनी रही। कुल उत्पादन में प्रतिशत के रूप में ईंधन के उपभोग में 2010-11 में 4.2 प्रतिशत पर लगातार गिरावट जारी रही। संगठित विनिर्माण में संसाधन गहनता बनी रही। उत्पादन के अपने कुल मूल्य में जीवीए का शेयर 1996-97 में 24.9 प्रतिशत के शीर्ष से धीरे-धीरे गिरकर 2010-11 में 17.8 प्रतिशत हो गई जो इसमें संसाधन गहनता खासकर कच्चा माल और अन्य ईंधन भिन्न निविष्टियों का संकेत देती है (चित्र 9.9)। आंतरिक बढ़ोत्तरी के

बॉक्स 9.2 : विनिर्माण में तेजी लाने हेतु सरकार की प्रमुख पहल

समग्र कारोबारी भावना को बढ़ाने और निवेश में तेजी लाने हेतु हाल में किए गए सरकार की पहल के अतिरिक्त, देश में उद्योग को सुदृढ़ करने और विशेषतया विनिर्माण क्षेत्र में कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में एक व्यापक कार्यनीति तैयार की गई है और औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु, मझौले और बड़े उद्योगों को कवर करते हुए सेक्टर विशिष्ट उपायों को अनुसंधित किया गया है। कुछ प्रमुख कदम जो देश के विनिर्माण क्षेत्र को बदल सकते हैं, में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी), दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन (डीएमआईसी) की घोषणा की गई है (अध्याय 2 देखें) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और ई-बिज परियोजना को बढ़ावा देने की नीतिगत सुधार की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी)

सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) अक्टूबर, 2011 में अनुमोदित की गई थीं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण शेर को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और इस दशक में अथवा आगे अतिरिक्त 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है। यह नीति उद्योगों पर विशेष बल देता है जो रोजगार युक्त हों, पूंजीगत वस्तुओं का सृजन करने, कार्यनीतिक महत्व, लघु और मझौले उद्यमों और उद्योग के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हों जहां भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ले सके। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कलस्टरों और समुच्चयन के संवर्धन कर व्यवस्था करत है खासकर राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के सृजन के माध्यम से। अब तक घोषणा की गई बारह राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों में से, आठ दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर के हैं। इसके अतिरिक्त, चार अन्य एनआईएम क्षेत्र को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है (i) महाराष्ट्र के नागपुर (ii) कर्नाटक के तुमकुर (iii) आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर और (iv) आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिला।

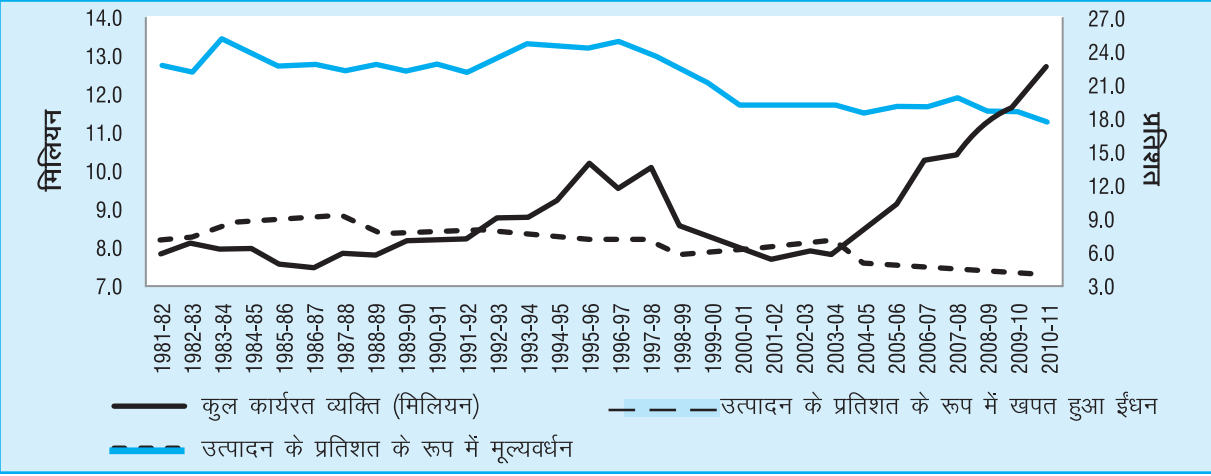
दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर डीएमआईसी परियोजना

वर्तमान में डीएमआईसी परियोजना के अंतर्गत औद्योगिक विकास पहल आठ औद्योगिक शहरों को कवर करता है जिन्हें रेलवे कोरिडोर के साथ विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में शुरू किए गए निवेश क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह मास्टर योजना गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को नए शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र को पूरा कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश में मास्टर योजना की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकारों ने नए औद्योगिक क्षेत्रों/क्षेत्रों और शुरुआती परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनों को पांच औद्योगिक शहरों के लिए प्रारंभ कर दिया है। समग्र डीएमआईसी परियोजना का विवरण अध्याय 2 में दिया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की पहलें

नीति सुधार पहल के एक भाग के रूप में, स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिक उद्योगों में एफडीआई को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आधार पर एफडीआई नीति को उत्तरोत्तर रूप से उदार बनाया जा रहा है। एफडीआई नीति में हुए कुछ परिवर्तनों में एकल दस्तावेज में नीति के समेकन के अलावा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 51 प्रतिशत तक मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई को शामिल करने, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत तक एफडीआई का विस्तार करना; नागर विमानन और विद्युत एक्सचेंजों में 49 प्रतिशत तक की एफडीआई; स्वतः मार्ग के अंतर्गत ब्रांडकास्टिंग सेक्टर में 49 प्रतिशत तक का एफडीआई और टेलीपोर्ट और मोबाइल टीवी के लिए सरकारी मार्ग के अंतर्गत 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक की एफडीआई शामिल है। कारोबार को आसान बनाने को बढ़ावा देने के लिए ई-बिज का गठन कर सरकार ने 'इन्वेस्ट इंडिया' के गठन की घोषणा की है-औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और फिक्की के बीच संयुक्त-उद्यम कम्पनी, एक अ-लाभ के रूप में सिंगल विंडो सुसाध्य-कारक, संभावनात्मक विदेशी निवेशकों हेतु और निवेश आकर्षित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में कार्य करना। इसके अलावा, सरकार ने ई-बिज योजना का कार्यान्वयन, कारोबारी उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सिंगल विंडो को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के तहत एक मिशन प्रणाली परियोजना प्रारंभ की है। ई-बिज पोर्टल की स्थापना का उद्देश्य अपने प्रचालन के सम्पूर्ण जीवन चक्र को कवर करते हुए कारोबारी उपयोगकर्ताओं को अनेक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का उद्देश्य सेवानुखी सेवाओं को घटनाक्रम-चालित जी2बी अन्तःक्रिया के माध्यम से भारत की कारोबारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

चित्र 9.9: संगठित विनिर्माण की विशेषताएं



लिए न केवल उच्च संसाधन सघनता है बल्कि अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) के लिए भी है।

9.23 संगठित विनिर्माण की लाभप्रदता उच्च संसाधन गहनता उपयोग से हुआ है जो कि मजदूरी और ब्याज दरों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल परिलब्धि 1980-81 में 40.6 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 22 प्रतिशत हो गई। कुल उत्पाद में परिलब्धियों का शेयर पिछले सात वर्षों में 19-22 प्रतिशत की रेंज में बना रहा। उत्पादन के प्रति ब्याज के शेयर में गिरावट भी रही है जो 1991-92 में 28.4 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 9.0 प्रतिशत हो गई। तत्पश्चात् 2010-11 में बढ़ कर 10.6 प्रतिशत हो गई। संगठित विनिर्माण की लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी के इन दो अनुपातों में कमी पर निर्भर रही है और 1991 में 18.5 प्रतिशत से 2010-11 में 47.8 प्रतिशत पर मंद रहने से पहले सुधरकर 2007-08 में 53.8 प्रतिशत पर आ गई। प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अतः संगठित विनिर्माण क्षेत्र के आंतरिक बढ़ोत्तरी के लिए ब्याज दर संरचना एक महत्वपूर्ण कारक है। वस्तुतः संस्थागत पूंजी के अपेक्षाकृत कम पहुंच वाले असंगठित विनिर्माण ब्याज दर वृद्धि के लिए अधिक संवेदनशील हो सकती है (चित्र 9.1)।

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

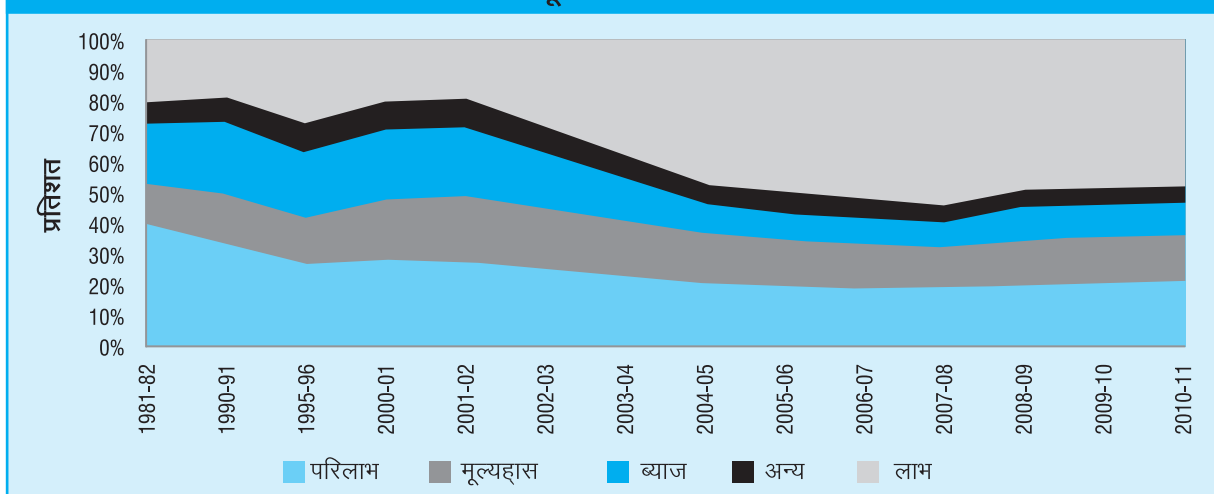
9.24 एमएसएमई पंजीकृत और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों का वर्गीकरण प्रत्येक उद्यम द्वारा संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मानदण्ड पर आधारित है। रोजगार, निवेश, उत्पादों, सकल उत्पाद और आयातों जैसे विभिन्न आर्थिक परिवर्ती संबंधी पंजीकृत एमएसएमई के लिए विस्तृत जानकारी एमएसएमई की चौथे गणना (2006-07) के पर आधार उपलब्ध है। इस पंजीकृत एमएसएमई का आकार

94.9 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों, 4.89 प्रतिशत लघु और 0.17 प्रतिशत मझौले उद्यमों के समानुपात में उप-क्षेत्रवार वाली लगभग 15.84 लाख ईकाईयों में होने का अनुपात लगाया गया था। कुल पंजीकृत एमएसएमई क्षेत्र 67.1 प्रतिशत विनिर्माण उद्यमों और 32.9 प्रतिशत सेवा उद्यमों से बना है। इन पंजीकृत उद्यमों का लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित था। असंगठित क्षेत्र ईकाईयों संबंधी चौथी गणना पर आधारित अधिक विस्तृत जानकारी, जो कि संपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 94 प्रतिशत है, आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

9.25 हाल के वर्षों में एमएसएमई संबंधी प्रधान मंत्री का कार्यबल और एमएसएमई बारहवीं योजना कार्य दल ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बारहवीं पंचवर्षीय योजना नीति फ्रेमवर्क को इन प्रमुख समितियों के सिफारिशों द्वारा कार्य निर्देशित किया जाता है। यह योजना एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को कवर करती है और इसकी प्रमुख सिफारिशें छः वृहत शीर्षों के अंतर्गत आती हैं अर्थात् (i) वित्त और ऋण (ii) तकनीकी (iii) अवसंरचना (iv) विपणन और अधिप्राप्ति (v) कौशल विकास और प्रशिक्षण, और (vi) संस्थागत संरचना। इस योजना में खादी और ग्रामीण उद्योगों और रेशा क्षेत्र की अलग सिफारिशें हैं। एमएसएमई क्षेत्र में तेजी लाने के लिए, प्रचालन के अंतर्गत निम्नलिखित सहित कई योजनाएं हैं। इसके आगे के सुधारों को जिन पर विचार किया जा सकता है, बॉक्स 9.3 में दर्शाया गया है।

1. **अधिप्राप्ति की नीति:** सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 द्वारा उत्पादित वस्तुओं और दी गई सेवाओं के लिए एक सरकारी अधिप्राप्ति की नीति को अधि सूचित किया है जिन्हें 1 अप्रैल, 2012 से लागू किया गया है।

चित्र 9.10: संगठित विनिर्माण के सकल मूल्य वर्धन के घटक



यह नीति अधिदेशित करती है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) एमएसई से उनके द्वारा अपेक्षित वस्तुओं/सेवाओं के वार्षिक मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिप्राप्त करेंगे। इसके अलावा, नीति ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमियों के स्थापित वाले एसएमई से 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अधिप्राप्त करने का उप-लक्ष्य भी चिन्हित किया है।

2. एमएसई कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीई):

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कम लागत पर एमएसई के सम्पूर्ण विकास हेतु कलस्टर अवधारणा को अपनाया है। साझा सहायता कार्रवाईयों हेतु एमएसएमई की क्षमता बढ़ाने के लिए विद्यमान कलस्टरों/नए उद्योग क्षेत्रों/संपदाओं अथवा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं में हल्के हस्तक्षेप किए जाते हैं। एमएसई-सीडीपी में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई ने 1 अप्रैल, 2012 से ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की है। नए विद्यमान औद्योगिक संपदाओं/कलस्टरों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करने और सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों का निर्माण करने के लिए ठोस हस्तक्षेप किए जाते हैं।

3. ऋण गारंटी योजना: सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खासकर संपार्श्विक अग्रिम/ तीसरे पार्टी गारंटियों के बगैर 100 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराकर लघु उद्यमों को ऋण गारंटी निधि योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना में ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों को आकर्षित करने के लिए, कई परिवर्तन किए गए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है (क) 100 लाख रुपए की ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी; (ख) 5 लाख रुपए तक ऋण हेतु 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर में बढ़ोत्तरी; (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऋण हेतु महिलाओं द्वारा स्थापित वाले/प्रचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर में बढ़ोत्तरी (घ) 5 लाख रुपए तक के ऋण हेतु 1.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक एक-बारगी गारंटी शुल्क 0.75 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक की वार्षिक सेवा प्रभारों में घटोत्तरी (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.5 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक एक बारगी गारंटी शुल्क में घटोत्तरी।

4. एमएसई हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पूंजी सहायता योजना से संबंधित ऋण (सीएलसी सदस्य): इस योजना का उद्देश्य संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए 15 प्रतिशत पूंजी सहायता (कम से कम 15 लाख रुपए तक) उपलब्ध कराकर एमएसई के तकनीकी अपग्रेडेशन को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के परिकलन के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100 लाख

रुपए है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 48 सुस्थापित उन्नत तकनीकियों/उप-सेक्टरों को अनुमोदित किया गया है। सीएलसीएसएस को भारतीय उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (टीआईसीसी), चेन्नई (टीआईआईसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम (एनएसआईसी) सहित 11 नोडल बैंकों/एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

9.26 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एक महत्वपूर्ण घटक उद्योग है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कुल मिलाकर 260 सीपीएसई हैं जिनमें से 225 प्रचालनरत हैं और 35 निर्माणाधीन हैं। वर्ष के दौरान, सकल ब्लाक के संदर्भ में सीपीएसई में कुल निवेश में औद्योगिक सीपीएसई का शेयर 77.46 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्ण अद्यतन परिणाम उपलब्ध हैं। 2011-12 के दौरान सीपीएसई ने खनन क्षेत्र में निवल लाभ में (29.45 प्रतिशत) सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की जबकि सीपीएसई ने विनिर्माण क्षेत्र में अपनी कुल बिक्री में 27.73 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद 2011-12 के दौरान निवल लाभ में 22.65 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। विद्युत क्षेत्र ने कुल बिक्री में 16 प्रतिशत की वृद्धि और लाभ में 13.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी 9.10)।

9.27 वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न सीपीएसई में विनिवेश द्वारा 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया और 13,854 करोड़ रुपए जुटाए गए जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) में 'बिक्री के लिए पेशकश' द्वारा विनिवेश शामिल किए गए और 12,749.50 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। 2012-13 के बजट में 30,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

9.28 सरकार ने एफडीआई के संबंध में निवेशक अनुकूल नीति बनाई है जिसके अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई है। एफडीआई नीति को अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के दृष्टिगत सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। संदर्भ सरल बनाने के लिए 1991 में जारी किए गए सभी प्रेस नोटों/परिपत्रों को एक दस्तावेज में समेकित किया गया है जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध है (www.dipp.nic.in)। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत वर्धमान रूप से आकर्षक और निवेशक हितैषी बना रहे, हाल के समय में एफडीआई नीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए

सारणी 9.10 : औद्योगिक सीपीएसई का निष्पादन, 2011-12

क्र.स.	सेक्टर			(₹ करोड़)
		2010-11	2011-12	प्रतिशत परिवर्तन
I.	विनिर्माण (28.31 प्रतिशत) @			
1.1)	कारोबार	947,411.7	1,210,087.6	27.7
1.2)	निवल लाभ	30,668.2	23,720.5	(22.7)
II.	खनन (23.53 प्रतिशत) @			
2.1)	कारोबार	15,968.3	188,011.1	17.7
2.2)	निवल लाभ	47,594.8	61,610.6	29.5
III.	विद्युत (25.62 प्रतिशत) @			
3.1)	कारोबार	84,032.4	97,623.0	16.2
3.2)	निवल लाभ	18,727.5	21,239.9	13.4

स्रोत : लोक उद्यम विभाग

टिप्पण: @ सकल ब्लाक के संदर्भ में कुल निवेश में प्रतिशत शेयर को दर्शाती है;

हैं। वर्ष 2012 के दौरान इस नीति में किए गए कुछ परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- (i) दिनांक 10.4.2012 से प्रभावी महत्वपूर्ण परिवर्तनों में यह शामिल हैं: (i) जिन्स बाजारों में एफडीआई स्कीम के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए ही एफआईपीबी का अनुमोदन अनिवार्य करना (ii) यह स्पष्टीकरण कि 'पट्टे' पर और वित्त' कवर होंगे 'प्रचालनरत पट्टे नहीं (iii) यह स्पष्टीकरण कि क्षेत्र की उच्चतम सीमा/वैधानिक उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 24 प्रतिशत की कुल सीमा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधधीन होगी।
- (ii) भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा जो अनिवासियों/अनिवासी कंपनी/अनिवासी कंपनियों द्वारा धारित और/अथवा नियंत्रित है, अधोप्रवाही निवेशों की गणना से संबंधित नीति की समीक्षा करते हुए सरकार ने कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना अथवा अन्य ऋण पुनर्संरचना तंत्र अथवा व्यापार बहियों अथवा ऋणों को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में गिनते हुए उनमें हुई चूकों के कारण शेयरों के अर्जन के अंतर्गत ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए अधोप्रवाही निवेशों की छूट दी है।
- (iii) सरकार ने निम्न से संबंधित शर्तों में संशोधन करते हुए एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार संबंधी नीति संशोधित की है: (i) यदि विदेशी निवेशक ब्रांड का स्वामी है: यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अब से आगे, सिर्फ एक अनिवासी कंपनी, चाहे वह ब्रांड की स्वामी है अथवा अन्यथा, उसे ब्रांड के स्वामी के साथ कानूनी रूप से तर्कसंगत करार के माध्यम से उस विशिष्ट ब्रांड के लिए एकल ब्रांड

उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति होगी और (ii) उत्पादों के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत का अनिवार्य स्रोतन भारतीय 'लघु उद्योगों/ग्रामीण और कुटिर उद्योगों, शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों से किया जाना है जो 51 प्रतिशत से अधिक की एफडीआई को शामिल करने वाले प्रस्तावों के संबंध में प्रयोज्य है। यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि क्रय किए गए माल की कीमत के 30 प्रतिशत का स्रोतन भारत से किया जाएगा और उसमें भी प्राथमिकता एमएसएमई, ग्रामीण और कुटिर उद्योगों, सभी क्षेत्रों में शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों को दी जाएगी।

- (iv) सरकार ने कतिपय शर्तों के अधधीन मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफआईपीबी के अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- (v) सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में उन विदेशी एयरलाइन, जिनकी चुकता पूंजी 49 प्रतिशत की सीमा तक है, जो अनुसूचित और अनुसूचित-भिन्न वायु परिवहन सेवाएं चला रही हैं, उन्हें भारतीय कंपनियों की पूंजी में भी निवेश करने की अनुमति का निर्णय लिया है।
- (vi) सरकार ने केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग (विद्युत विपणन) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत केंद्रों में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है यह विदेशी निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) विनियमों; अन्य प्रयोज्य कानूनों/विनियमों; प्रतिभूति और अन्य सोपाधिकताओं के अनुपालन में होगी।

(vii) सरकार ने उन एनबीएफसी, जिनका (i) विदेशी निवेश 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत से कम है और (ii) 50 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पंजीकरण है, को प्रचालनरत सहायक कंपनियों की संख्या पर किसी सीमा के बगैर और अतिरिक्त पूंजी लाए बगैर कतिपय एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए स्टेप डाउन सहायक कंपनियां गठित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह

9.29 अप्रैल-नवम्बर 2012-13 के दौरान एफडीआई का अंतर्वाह (इक्विटी अंतर्वाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी) पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत गिरकर 24.65 बिलियन अमरीकी डालर था (सारणी 9.11)। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए 15.85 बिलियन अमरीकी डालर थे। अप्रैल 2000 से नवम्बर 2012 तक एफडीआई अंतर्वाह की संचयी राशि 277.86 बिलियन अमरीकी डालर रही है।

9.30 अप्रैल-अक्टूबर, 2012 के दौरान सेवा, होटल और पर्यटन, धातुकर्म उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग, निर्माण, औषध एवं भेषज, औद्योगिक मशीनरी वे क्षेत्र थे जिन्होंने अधिकतम निवेश आकर्षित किया। उद्योग और अवसंरचना में क्षेत्रवार एफडीआई अंतर्वाह राशि सारणी 9.12 में दी गई है।

9.31 एफडीआई के इक्विटी निवेशों में प्रथम दस निवेश करने वाले देशों में मारीशस शीर्ष पर है उसके बाद सिंगापुर, यू.के., जापान, यू.एस., नीदरलैंड, साइप्रस, जर्मनी, फ्रांस और यू.एई का स्थान आता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2012 की अपनी वैश्विक प्रवृत्तियों और एफडीआई अंतर्वाहों की सतत वृद्धि में भारत 2012-14 के लिए तीसरा सर्वाधिक आकर्षक स्थान बना हुआ बताया गया है।

उद्योग-पर्यावरण संबंध

9.32 भारत में विविधिकृत औद्योगिक संरचना के विकास ने पर्यावरण पर दबाव उत्पन्न किया है जो बड़े और छोटे-छोटे स्तर के उद्योगों और बढ़ती हुई शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के मेल पर आधारित है तथा जो वायु, जल और भूमि के अपकर्ष के बढ़ते हुए दृष्टांतों में प्रदर्शित हुआ है। औद्योगिक प्रदूषण उद्योगों में पेट्रोलियम रिफाइनरी, वस्त्र, लुगदी और कागज, औद्योगिक रसायन, लौह और इस्पात तथा गैर-धात्विक खनिज उत्पाद। लघु उद्योग, विशेष रूप से धुलाई घर, रसायन विनिर्माण, ईंटें बनाना भी महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं। विद्युत क्षेत्र में, ताप विद्युत, जो बिजली उत्पादन की अधिकांश संस्थापित क्षमता का निर्माण करती है, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, नीतियों और निवेश का चयन, इस प्रकार होना चाहिए जो संसाधनों के अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग, कम संसाधनों के अलावा अतिरिक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को अपनाना और पर्यावरण संबंधी प्रभाव को कम करने के लिए प्रथाओं को प्रोत्साहित करे।

श्रमिक संबंध

9.33 केन्द्र व राज्यों, दोनों के औद्योगिक संबंधों की मशीनरियों के सतत प्रयासों के कारण, औद्योगिक संबंधों का माहौल सामान्यतः शांत और सौहार्दपूर्ण रहा है। जबकि 2007 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के दृष्टांतों की संख्या 389 थी, परंतु यह संख्या अक्टूबर, 2011 में 189 (अनंतिम) थी और अक्टूबर 2012 तक यह 194 (अनंतिम) पर थी इसने इस अवधि के दौरान कमी का रुख प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार, गंवाए गए मानव दिवसों की संख्या 2007 में 27.17 मिलियन

सारणी 9.11 : विदेशी अंतर्वाह

वित्तीय वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार	प्रतिशत वृद्धि	(बिलियन अमरीकी डालर)	
			एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह	प्रतिशत वृद्धि
2003-4	4.32	(-) 14	2.19	(-) 19
2004-5	6.05	(+) 40	3.22	(+) 47
2005-6	8.96	(+) 48	5.54	(+) 72
2006-7	22.83	(+) 146	12.49	(+) 125
2007-8	34.84	(+) 53	24.58	(+) 97
2008-9	41.87	(+)20	31.40	(+)28
2009-10 (अ)	37.75	(-)10	25.83	(-)18
2010-11 (अ)	34.85	(-)08	21.38	(-)17
2011-12(अ)	46.55	(+)34	35.12	(+)64
2012-13 (अ) (अप्रैल-नवम्बर)	24.65		15.85	

स्रोत : डीआईपीपी

अ: अनंतिम

सारणी 9.12 : उद्योग और अवसंरचना में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1991-2000	2000-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-अक्तू. 2011-12	अप्रैल-अक्तू. 2012-13
खाद्य उत्पाद	707.4	1237.3	246.9	239.7	122.3	368.4
सन्धान उद्योग	24	770.1	57.7	69.7	53.1	43.7
वस्त्रोद्योग	241.8	828.6	129.8	164.7	74.3	91.3
काष्ठ उत्पाद	0.0	18.8	1.6	29.6	8.1	28.7
कागज	250.5	716.9	44.0	454.7	29.6	3.1
चमड़ा	33.5	42.6	9.3	8.3	5.6	34.7
रसायन	1480.9	4446.1	2690.2	7534.1	7007.6	789.4
रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद (तेल की खोज सहित)	90.3	2953.6	573.6	2217.4	2097.8	476.3
अधात्विक खनिज	261.1	2263.6	657.3	310.0	203.4	189.7
धातुएं और धात्विक उत्पाद	186.2	3143.2	1098.1	1786.1	1436.9	1215.1
मशीनरी एवं उपस्कर	2043.1	15670.4	1836.3	4147.5	2894.2	1171.2
परिवहन उपस्कर	0	4603.2	1299.4	923.0	563.7	743.2
अन्य विनिर्माण	1761.6	5705.6	1495.6	850.5	625.7	206.3
खनन (खनन सेवाओं सहित)	0	730.9	79.5	142.7	135.0	15.9
विद्युत*	1038.9	5220.9	1486.2	2104.6	1440.8	771.0
दूरसंचार	1089.4	8915.9	1664.5	1997.2	1964.1	48.4
जोड़	9208.7	57267.7	13369.9	22979.7	18662.0	6196.4

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

टिप्पणी : इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई) स्कीमों और सेवा क्षेत्र से संबंधित अंतर्वाह शामिल नहीं है।

* इसमें अपरंपरागत ऊर्जा शामिल है।

और अक्टूबर, 2012 तक 2.03 मिलियन (अनंतिम) थीं (सारणी 9.13)। हड़तालों, तालाबंदियों के स्थानिक/उद्योगवार छितराव के संबंध में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में

व्यापक भिन्नताएं हैं। मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक, अनुशासन और हिंसा तथा वित्तीय तंगी इन हड़तालों और तालाबंदियों के प्रमुख कारण माने गए हैं।

सारणी: 9.13 : हड़तालें और तालाबंदियां (नष्ट हुए मानव-दिवस)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियां	नष्ट हुए कुल मानव-दिवस
2007	210	179	2,71,66,752
2008	240	181	1,74,33,721
2009(अ)	205	187	1,33,64,757
2010(अ)	261	168	1,79,32,345
2011(अ)	106	29	66,71,179
2012 (जनवरी-अक्टूबर)(अ)	173	21	20,29,439

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय

टिप्पणी : अ-अनंतिम

चुनौतियां और संभावनाएं

9.34 वर्ष 2011-12 में औद्योगिक उत्पादन सुस्त बना रहा और यह मंदी चालू वित्त वर्ष के दौरान भी बनी हुई है। औद्योगिक वृद्धि अभी भी कमजोर बनी हुई जो अनेक घरेलू कारकों और बाह्य झटकों के कारण है। अवसंरचना और ऊर्जा की अड़चनें, भारत के निर्यात हेतु मांग में गिरावट और निवेश में कमजोर मांग जोखिमकारी कारक हैं। नवीनतम अग्रणी संकेतक, यद्यपि कुछ सुधार दर्शाते हैं परन्तु अभी ये आरंभिक हैं और इन्हें बनाए रखे जाने की जरूरत होगी। हाल के महीनों में सरकार द्वारा की गई कुछ नीतिगत पहलों द्वारा व्यवसाय माहौल मजबूत होने से कुछ उम्मीद की किरण जगी है। औद्योगिक उत्पादन की नवीनतम मौसमी रूप से एकत्रित वार्षिकीकृत वृद्धि चालू वर्ष में 3 प्रतिशत के आसपास संतुलित रूप से सकारात्मक है जो यह इंगित करती है कि शीघ्र ही इसका तीव्र गति पकड़ना मुश्किल है।

9.35 अल्पावधि में उद्योग और महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश का पुनरुद्धार बड़ी चुनौती है। औद्योगिक क्षेत्र लगातार दूसरे वर्ष निवेश में मंदी से बुरी तरह आहत हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार 2011-12 के दौरान (2004-05 के मूल्यों पर) विनिर्माण क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 2010-11 की तुलना में 18.8 प्रतिशत तक गिरा है। महत्वपूर्ण उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में अप्रैल-अक्टूबर 2012 के दौरान 6.19 बिलियन डालर पर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 18.66 बिलियन डालर के अंतर्वाह की तुलना में, निम्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों ने इन क्षेत्रों में निवेश को और अवरुद्ध कर दिया है। दर्ज किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन में इंगित किए गए निवेश आशय, जो उद्योग में संभावित निवेश प्रवाहों के अग्रणी संकेतक हैं, 2011 और 2012 में कम हुए हैं। तो भी, हाल के महीनों में औद्योगिक क्षेत्र में सकल बैंक ऋण लगने में मामूली सुधार दिसंबर अंत 2012 में सकल बैंक ऋण लगने में वर्षानुवर्ष वृद्धि एक वर्ष पूर्व 19.8 प्रतिशत की तुलना में 13.8 प्रतिशत रही थी।

9.36 कमजोर निवेश माहौल के अलावा अवसंरचना की अड़चनों के कारण औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन कमजोर बना हुआ है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तीव्र गिरावट, कोयला क्षेत्र में कम निष्पादन और ताप विद्युत उत्पादन पर इसके परिणामी प्रभाव; रेल, सड़क और पत्तनों आदि में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मंद गति के कारण औद्योगिक वृद्धि दर में मंदी रही है। मध्यावधि में इसलिए यह महत्वपूर्ण होगा कि बड़े क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाया जाए और सामरिक बड़ी राशि वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए।

9.37 जैसा कि पूर्ववर्ती भागों में विस्तार से चर्चा की गई है, हाल की औद्योगिक मंदी का महत्वपूर्ण ठोस कारण विनिर्माण क्षेत्र रहा है सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में भारत का विनिर्माण मूल्य वर्धन लगभग 15 प्रतिशत पर दृढ़ बना हुआ है। यूनिडो द्वारा 2009 के लिए संकलित नवीनतम प्रतिस्पर्धी औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के अनुसार 118 देशों में भारत का स्थान 42वां था। शीर्ष दस विनिर्माण राष्ट्रों में से एक होने के बावजूद भारत का निम्न प्रतिस्पर्धी औद्योगिक निष्पादन का स्थान मूल कमजोरियों और दोषपूर्णताओं को इंगित करती है। अतः भारत के विनिर्माण क्षेत्र को

अग्रणी निर्माताओं में से एक बनने के लिए गतिशीलता और प्रौद्योगिक परिष्करण अपनाने की जरूरत है। दूरगामी दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं विकास का निम्न स्तर और कुशल मानव शक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और विनिर्माण संवृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी।

9.38 व्यवसाय करना सुखद बनाने के अर्थ में भारत ने महत्वपूर्ण रूप से सुधार नहीं किया है और अन्य औद्योगिक अभिजात देशों की तुलना में अभी भी इसका स्थान बहुत नीचे है। खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र बहुविध अनुमोदन और प्रचालनात्मक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। व्यवसाय स्थापित करने और इसे छोड़ने की प्रक्रिया वक्त लगने वाली और जटिल है जिसमें खर्चीले तीसरे पक्षकार की मदद लेनी पड़ती है। चूँकि राज्य एमएसएमई क्षेत्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए विद्यमान पारिस्थितिकी प्रणाली एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निकासी के नियम जटिल व मंहगे हैं और संसाधनों के पुनर्आवंटन से लाभ लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

9.39 प्रतिस्पर्धी लागत पर वित्तपोषण का स्रोतन संगठित और एमएसएमई उद्यम दोनों के लिए दूसरी बड़ी अड़चन हैं। आंतरिक उपचित सामग्री के माध्यम से इतर वित्तपोषण महंगा और निषेधात्मक है। एमएसएमई संबंधी प्रधानमंत्री के कृतिक दल ने वृद्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्षानुवर्ष वृद्धि की सिफारिश की थी। इसने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत के आवंटन की भी सिफारिश की थी जिसे चरणबद्ध रूप से प्राप्त किया जाना है। तथापि, संसाधन प्रवाह में सुधार करने की जरूरत होगी। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों की भी गति बढ़ाने की जरूरत होगी। वर्तमान में देश में थोड़ी सी संख्या में ही उष्मायित्र काम कर रहे हैं जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हैं। सरकारी-निजी-भागीदारी आधार पर नए उष्मायित्रों की स्थापना की जरूरत पड़ेगी। अधिक निवेश व प्रतिभा आकर्षित करने के लिए उष्मायित्रों से निवेशकों को वापस लाभ दिए जाने की अनुमति दिए जाने की जरूरत है। इन कुछेक परिवर्तनों से औद्योगिक वृद्धि और संतुलित हो सकती है।